

राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न वर्गों को मिलेंगी सौगातें

उपचुनाव की सात विधानसभा सीटों का परिणाम आज

■ जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और इंद्रगढ़ पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी

18 से 22 राउंड में गिनती होगी। 13 नवंबर 2024 को हुए मतदान में 7 सीटों पर औसतन कुल 69.72 प्रतिशत वोटिंग हुई थी।

वहीं, 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में 74.74 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। सात सीटों में से 6 सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई थी। इन सात में सबसे ज्यादा 75 प्रतिशत से अधिक मतदान खींवर और रामगढ़ सीट पर हुआ था।

वहीं, खींवर सीट पर उपचुनाव में विधानसभा चुनाव 2023 से 2.13 फीसदी ज्यादा वोटिंग हुई थी। खींवर सीट पर 2023 के मतदान प्रतिशत 73.49 की तुलना में अब उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 75.8 हो गया। दौसा सीट पर पिछली बार से 12.10 प्रतिशत कम वोट वोटिंग हुई थी।

हुई थी। सिल्वर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुवेर खान का निधन होने की वजह से सीट खाली हुई है।

ईवीएम से वोटों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू की जाएगी। इसके लिए 98 टेबल लगाई गई हैं। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 141 राउंड में ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। वोटर्स की संख्या के आधार पर

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के जरिये युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विभिन्न कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं योजनाओं का शुभारम्भ कर विशेष सौगातें दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार भी मौजूद थे।

विकसित राजस्थान' के आयोजन में युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक एवं पशुपालकों को दी जाने वाली विभिन्न सौगातों की समीक्षा की। शर्मा ने

अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जाना

सुनिश्चित करें। शर्मा ने निर्देश दिए कि राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विकास प्रदर्शनियों में राज्य सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी

■ युवा, किसान एवं महिला कल्याण हमारी प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

■ आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में दिए दिशा-निर्देश

योजनाओं, विकास कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आकर्षक तरीके से प्रदर्शित की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनकी जानकारी प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान होने वाले विभिन्न लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यों की भी समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

झुंझुनू बी.डी.के. अस्पताल के पी.एम.ओ. सहित तीन चिकित्सक निलम्बित

जयपुर। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल की आपातकालीन इकाई में एक जीवित युवक को मृत घोषित करने के प्रकरण को स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही मानते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर से निर्देश पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया है। प्रकरण में झुंझुनू कलेक्टर द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विभाग ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप पंचार, डॉ. योगेश कुमार जाखड़ एवं डॉ. नवनीत मील को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गयी है।

अडानी की गिरफ्तारी की मांग

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि सेबी के अमेरिकी समकक्ष, प्रतिभूति विनियम आयोग का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके सात सहयोगियों ने भारत में उच्च-मूल्य वाले सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए 2,000 करोड़ (250 मिलियन) की रिश्वतखोरी की योजना बनाई। ऐसे में इस मामले की जांच कर मामले की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। डोटसरा ने कहा कि अडानी पर आरोप लगाने पर भाजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संदेश के धरे में आता है। उन्होंने अडानी की गिरफ्तारी करने की मांग की है। डोटसरा ने कहा कि अमेरिकी अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2020 और 2024 के बीच, अडानी और उनके सह-प्रतिवादिियों ने 16,000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय सरकार की अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की।

ई.आर.सी.पी. का शिलान्यास भी हम करेंगे और लोकार्पण भी हम करेंगे : सुरेश रावत

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष के ईआरसीपी पर दिये गये बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी बयानवीर ईआरसीपी पर अपने झूठे बयानों से जनता को गुमराह नहीं करा। भजनलाल सरकार ईआरसीपी के सपने को साकार करने का कार्य कर रही है और जल्द ही शिलान्यास होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार द्वारा 10 हजार करोड़ के कार्यों को शीघ्र आरम्भ कराये जाने हेतु शिलान्यास कराया जाएगा।

- 'कांग्रेसी बयानवीर झूठे बयानों से जनता को गुमराह नहीं करे'
- 'पूर्ववर्ती सरकार ने ईआरसीपी पर जनता को गुमराह किया जिसका नतीजा सबके सामने है'
- 'हमारी सरकार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 10 हजार करोड़ के कार्यों के शीघ्र शिलान्यास करेगी'

कांग्रेस सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इनकी मंशा इसे आगे बढ़ाने की नहीं थी। अब हम इन कार्यवाहियों को शीघ्र ही पूरा करने जा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष झूठे आंकड़ों से खेलना बंद करो। ईआरसीपी के लिए इनकी सरकार के समय 10 हजार करोड़ रूपए देने के कागजात जनता के सामने रखे ताकि जनता को इनकी कथनी और करनी में अंतर पता चल सके। क्योंकि होटलों में समय बिताने वाले इन बयानवीरों ने अपने बयानों से ही राजस्थान का विकास किया था। जिसका जनता ने धूल चटा दी और आज कांग्रेस उपचुनाव में भी इन झूठे बयानवीरों के कारण चुनाव हार रही है।

रावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रीय परियोजना में स्वीकृति किये जाने का सन्दर्भ देकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ईआरसीपी

योजना (पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना-एकीकृत ईआरसीपी) को भारत सरकार द्वारा नदी जोड़ो परियोजना में शामिल किया गया है। भारत सरकार की नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। इसके अन्तर्गत सिंचाई, पेयजल लाभों को शामिल करते हुए इसे

वृहद रूप दिया है। जल संसाधन मंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेसी ईआरसीपी परियोजना पर बयान देने से पहले अपनी गिरेबां में झांक लेते कि वननेला-बैराज-ईसरदा बांध का कार्य हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा आरम्भ कर दिया गया था परन्तु पूर्ववर्ती

कांग्रेसी सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इनकी मंशा इसे आगे बढ़ाने की नहीं थी। अब हम इन कार्यवाहियों को शीघ्र ही पूरा करने जा रहे हैं।

यू.टी.बी कार्मिकों का भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन

जयपुर। यूटीबी कार्मिक एक बार फिर सरकार और प्रशासन के खिलाफ लातमबंद हो गए हैं। शुक्रवार को यूटीबी कार्मिकों ने बड़ी संख्या में प्रदेश भाजपा कार्यालय और स्वास्थ्य भवन पर विरोध प्रदर्शन किया। यूटीबी कार्मिक सुबह 11 बजे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और करीब चार घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद यूटीबी कार्मिकों को भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने वार्ता के लिए बुलाया और यूटीबी कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान यूटीबी कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

भर्तियों में मुद्दों के निस्तारण के लिए क्यों ना एस.ओ.पी. व विभागीय कमेटी बने : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में विभिन्न मुद्दों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने और इसमें देरी होने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से कहा है कि क्यों ना अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए एक एसओपी तैयार की जाए। वहीं हर सरकारी विभाग में शिकायत निवारण कमेटीयां बनाई जाए जो अभ्यर्थियों की शिकायतों का शुरुआती स्तर पर ही निस्तारण कर सकें। अदालती आदेश के पालना में प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ और प्रमुख विधि सचिव ब्रजेन्द्र कुमार जैन अदालत में उपस्थित हुए। मेडिकल

- 'हर सरकारी विभाग में शिकायत निवारण कमेटीयां बनाई जाए जो अभ्यर्थियों की शिकायतों का शुरुआती स्तर पर ही निस्तारण कर सकें'

विभाग की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने कहा कि विभाग की भर्तियों में अस्थायी सूची जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से परिवेदनाएं ली जाती हैं और ई-हैंड परिवेदना कमेटी के पास भेजा जाता है। इसके बाद ई-हैंड नीति निर्धारण समिति में रखा जाता है। वहीं विधि विभाग की ओर से कहा गया कि एडोके भर्ती में भी आपत्तियों का निस्तारण किया

और राज्य सरकार के विभागों से चर्चा कर एसओपी बनाई जा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरपीएससी के कार्यशील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अखबारों की खबरों से पता चल रहा है कि आरपीएससी में चयन कैसे हो रहे हैं। वहां पर पारदर्शिता की कमी है और भेदभाव होता है। कई बार जिन अभ्यर्थियों के लिफाफे परीक्षा में कम अंक होते हैं उनके साक्षात्कार में ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं। वहीं अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर मामले की सुनवाई 28 नवंबर को तय की है।

ज्योति कलश रथ यात्रा का स्वागत

जयपुर। टीम 39 "जहां चाह वहां राह" जन कल्याण ट्रस्ट पानीपंच द्वारा गायत्री तीर्थ शान्तिकुंज हरिद्वार से देश के 2400 तीर्थों के पवित्र जल-रज के साथ ज्योति कलश रथ का शुक्रवार को सुबह स्वर्णकार सेवा सदन, आर.पी.ए रोड पर टीम 39 द्वारा पुष्प वर्षा करके व आरती द्वारा स्वागत किया गया। टीम 39 के मीडिया प्रभारी मनीष केडिया व प्रधान ट्रस्टी विष्णु बियानी ने बताया कि कार्यक्रम में नेहरू नगर विकास समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ताराचंद खडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष संजीव सरोलिया भंवरलाल मीणा मौजूद थे।



जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित तानसेन समारोह में तबला वादकों ने अपनी प्रस्तुति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया।

ज्यादा से ज्यादा कृषकों को दिया जाये प्रशिक्षण : राजन विशाल

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इन्वेषन एण्ड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा कर अधिकारियों को ट्रेनिंग सेंटर में ज्यादा से ज्यादा कृषकों को उन्नत तकनीकी का कृषि प्रशिक्षण देने के लिए कहा।



शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने शुक्रवार को दुर्गापुरा स्थित इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इन्वेषन एण्ड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया।

किसानों की पोषण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। इस समन्वित कृषि प्रणाली क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसल पद्धतियां, उद्यानिकी फल एवं सब्जियां, डेयरी यूनिट, बकरी यूनिट, पोल्ट्री यूनिट, अजोला यूनिट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट और गोबर खाद यूनिट है।

समन्वित कृषि प्रणाली के मुख्य शष्य वैज्ञानिक डॉ. उममदे सिंह ने किसानों के लिए सालभर आय का अच्छा स्रोत

होने एवं किसान के परिवार के लिए पोषण युक्त भोजन जैसे फल, सब्जी, अनाज, दाल, मोटे अनाज, तिलहन, पशुओं के लिए चारा एवं इससे जलित अपशिष्ट के सदुपयोग हेतु वर्मी कम्पोस्ट, गोबर की खाद इत्यादि के रूप में प्रयोग करने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार एवं बाहरी उर्वकों पर निर्भरता कम करने की जानकारी दी। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बलराज सिंह ने कृषि विश्वविद्यालय एवं दुर्गापुरा में संचालित विभिन्न कृषि

राइजिंग राजस्थान से प्रदेश की पूरे देश में उभरेगी नई पहचान : भजनलाल शर्मा

■ समिट के सुनियोजित आयोजन एवं ब्रांडिंग के लिए विस्तृत निर्देश

■ 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' की तैयारियों की समीक्षा बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का वृहद स्तर पर आयोजन करने जा रही है तथा इस समिट के माध्यम से प्रदेश की पूरे देश में एक नई पहचान उभरेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का सुनियोजित एवं भव्य स्तर पर आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह समिट निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही पूरे देश में अपनी छाप छोड़ सके।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समिट के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए कार्य निर्धारण के साथ अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए। शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल

इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट से लेकर विभिन्न कार्यक्रम स्थलों के रास्तों पर आकर्षक होर्डिंग्स एवं बैनर लगाए जाएं। साथ ही, समिट में कंट्री पार्टनर के तौर पर शामिल होने वाले देशों की जानकारी को भी प्रमुख स्थानों पर विशेष रूप से दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने आतिथ्य-सत्कार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि समिट में भाग लेने के लिए आने वाले ब्रांड एम्बेसेडर, निवेशकों एवं अन्य अतिथियों को सरल एवं सहज सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। साथ ही, उन्होंने उद्घाटन सत्र के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों, अतिथियों की बैठक व्यवस्था तथा अन्य तैयारियों के विषय में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

